3. मौद्रिक नीति के उपकरण
(INSTRUMENTS OF MONETARY POLICY)

मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए साख-नियंत्रण उपायों से सम्बन्ध रखती है। ये दो प्रकार के होते हैं : *(i)* मात्रात्मक (quantitative)— सामान्य अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण; *(ii)* गुणात्मक (qualitative)—चयनात्मक अथवा प्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार के प्रचालन तथा परिवर्तनशील आरक्षण आवश्यकताएं सम्मिलित रहती हैं। उनका उद्देश्य कमर्शियल बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में साख के सम्पूर्ण स्तर का नियमन (regulate) करना है। इनमें परिवर्तनशील सीमा आवश्यकताएं तथा उपभोक्ता साख का नियमन शामिल रहते हैं।

(1) बैंक दर नीति (Bank Rate Policy)—बैंक दर, केन्द्रीय बैंक द्वारा उधार देने की वह न्यूनतम दर है जिस पर वह विनिमय की प्रथम श्रेणी हुण्डियों तथा कमर्शियल बैंक द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों को पुनः बट्टा (rediscount) करता है। जब केन्द्रीय बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था के भीतर स्फीतिकारी दबाव प्रकट होने शुरू हो गए हैं, तो वह बैंक-दर बढ़ा देता है। केन्द्रीय बैंक से उधार लेना महंगा हो जाता है और कमर्शियल बैंक उससे अपेक्षाकृत कम उधार लेंगे। कमर्शियल बैंक आगे व्यापारियों को उधार देने की अपनी दरें बढ़ा देते हैं। इस कारण उधार लेने वाले कमर्शियल बैंकों से कम उधार लेंगे। साख का संकुचन होता है और कीमतें और आगे बढ़ने से रुक जाती हैं। इसके विपरीत, जब कीमतें गिर जाती हैं, तो केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक दर घटा देता है। कमर्शियल बैंकों को केन्द्रीय बैंक से उधार लेना सस्ता रहता है, तब कमर्शियल बैंक भी अपनी उधार देने की दरें घटा देते हैं। इससे व्यापारियों को अधिक उधार लेने को प्रोत्साहन मिलता है। निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। उत्पादन, रोजगार, आय तथा मांग बढ़ना शुरू करती हैं और कीमतों का गिरना रुक जाता है।

(2) खुले बाजार के प्रचालन (Open Market Operations)—खुले बाजार के प्रचालन मुद्रा बाजार में केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय से संबध रखते हैं। जब कीमतें बढ़ने लगती हैं और उन्हें रोकने की जरूरत होती है तो केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियां बेचता है। कमर्शियल बैंकों के आरक्षण (reserve) घट जाते हैं और वे व्यापारी वर्ग को और उधार देने की स्थिति में नहीं रह जाते। आगे निवेश हतोत्साहित होता है और कीमतों में वृद्धि रुक जाती है। इसके विपरीत, जब अर्थव्यवस्था में सुस्ती (recession) की शक्तियां शुरू होती हैं, तो केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियां खरीदता है। कमर्शियल बैंकों के आरक्षण बढ़ जाते हैं। वे अधिक उधार देते हैं, निवेश, उत्पादन, रोजगार तथा मांग बढ़ जाती हैं और कीमतों का गिरना रुक जाता है।

(3) रिज़र्व अनुपातों में परिवर्तन (Changes in Reserve Ratios)—इस औजार का सुझाव केन्ज ने अपनी पुस्तक *Treatise of Money* में दिया था और संयुक्त राज्य अमरीका पहला देश था जिसने इसे मौद्रिक तरीके के रूप में अपनाया। कानून के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत अपने तहखानों में रिजर्व कोष में और कुछ प्रतिशत केन्द्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो केन्द्रीय बैंक रिजर्व अनुपात बढ़ा देता है। बैंकों को केन्द्रीय बैंक के पास अधिक राशि रखनी पड़ती है। उनके आरक्षण घट जाते हैं और वे कम उधार देते हैं। निवेश, उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत स्थिति में जब रिजर्व अनुपात घटाया जाता है, तो कमर्शियल बैंकों के आरक्षण बढ़ जाते हैं। वे अधिक उधार देते हैं और आर्थिक क्रिया पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

Scanned with CamScanner

(4) *चयनात्मक साख नियन्त्रण (Selective Credit Control)*—विशिष्ट उद्देश्यों से विशेष प्रकार की साख को प्रभावित करने के लिए चयनात्मक साख नियन्त्रण काम में लाये जाते हैं। अर्थव्यवस्था के भीतर सट्टा क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए वे सामान्यत: परिवर्तनशील सीमा आवश्यकताओं (changing margin requirements) का रूप ले लेते हैं। जब अर्थव्यवस्था में अथवा विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ वस्तुओं में तेज सट्टा क्रिया होती है और कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो केन्द्रीय बैंक उन पर सीमा आवश्यकता बढ़ा देता है। परिणाम यह होता है कि उधार लेने वालों को विशिष्ट प्रतिभूतियों पर ऋण के रूप में कम मुद्रा दी जाती है। उदाहरणार्थ, सीमा आवश्यकता को बढ़ा कर 60 प्रतिशत कर देने का अर्थ है कि 10,000 रु. मूल्य की प्रतिभूतियों के प्राधिदाता (pledger) को उनके मूल्य का 40 प्रतिशत (4,000 रु.) ऋण के रूप में दिया जाएगा। विशिष्ट क्षेत्रों में सुस्ती की स्थिति में, केन्द्रीय बैंक सीमा आवश्यकताएं घटाकर उधारग्रहण को प्रोत्साहन देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रभावशाली विश्लेषणात्मक मौद्रिक नीति के लिए आवश्यक है कि बैंक दर, खुले बाजार के प्रचालन, रिजर्व अनुपात तथा विशिष्ट नियन्त्रण उपायों को एक ही साथ अपनाया जाए। परन्तु सभी मुद्रा सिद्धांतकारों ने स्वीकार किया है कि: *(i)* मन्दी में जब व्यापार विश्वास अपनी क्षीणतम दशा में होता है, तब मौद्रिक नीति की सफलता शून्य होती है; और *(ii)* स्फीति के विरुद्ध वह सफल रहती है। मुद्रावादियों का कहना है कि राजकोषीय नीति के मुकाबले मौद्रिक नीति में अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन होता है। उसे शीघ्र कार्यान्वित किया जा सकता है।

4. विस्तारक मौद्रिक नीति
(EXPANSIONARY MONETARY POLICY)

विस्तारक (या **सस्ती**) मौद्रक नीति का उपयोग अवस्फीतिक अन्तराल (deflationary gap) या मंदी या सुस्ती (recession) से निकलने के लिए होता है। जब वस्तुओं और सेवाओं की उपभोक्ता मांग और निवेश वस्तुओं की व्यवसाय मांग में गिरावट आती है तो अवस्फीतिक अन्तराल प्रकट होता है। केन्द्रीय बैंक विस्तारक मौद्रिक नीति प्रारम्भ करता है जो साख बाजार की दशाओं को आसान बनाती है और समस्त मांग में ऊपर की ओर परिवर्तन लाती है। इस उद्देश्य के लिए, केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, सदस्य बैंकों की रिज़र्व आवश्यकताएं कम करता है, बट्टा दर कम करता है तथा चयनात्मक साख उपायों द्वारा उपभोक्ता और व्यवसाय साख को प्रोत्साहित

Scanned with CamScanner